



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 20, 2013/वैशाख 30, 1935

No. 111]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 20, 2013/VAISAKHA 30, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)
जांच शुरुआत अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 मई, 2013

विषय:— चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “सभी व्यास के ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क की जांच प्रारंभ करना।

सं. 14/02/2013—डीजीएडी:—समय—समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1995 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) तथा समय—समय पर यथा संशोधित, सीमा शुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1975 (जिसे एतदपश्चात पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) के अनुसार मै. एच ई जी लिमिटेड और मै. ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड (जिन्हें एतदपश्चात “याचिकाकर्ता” अथवा “आवेदक” कहा गया है) ने सामूहिक रूप से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष, चीन.गण. (जिसे एतदपश्चात सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स (जिसे एतदपश्चात सम्बद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटन जांच प्रारंभ करने के लिए एक आवेदन पत्र (जिसे याचिका भी कहा गया है) दायर किया है।

विचाराधीन उत्पाद

2. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. से आयातित “सभी व्यास के ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स” है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का मुख्य कार्य भट्टियों में चार्ज फेड में विद्युत धारा प्रवाहित करके इस्पात को पिघलाने के लिए इनको प्रयोग करना है। इस्पात निर्माण की इस पद्धति को द्वितीयक इस्पात निर्माण के रूप में भी जाना जाता है। आर्क फरनेसेस में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का प्रयोग विद्युत धारा सुचालक के रूप में होता है और इनसे अपेक्षा की जाती है कि वे बहुत उच्च दर की विद्युत फीड के वाहक होंगे। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्सको व्यापक रूप से अल्ट्रा हाई पावर (यूएचपी) तथा अन्य, जिनमें शामिल हैं हाईपावर ग्रेड (एचपीजी) और सामान्य पावर ग्रेड (एनपीजी), के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तदुनसार, उनसे इतना उच्च करंट तथा पावर फीड्स के योग्य गुणधर्म होने की अपेक्षा की जाती है तथा उन्हें अध्याय शीर्षक 85.45 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इस विचाराधीन उत्पाद का आयात प्राथमिकता 85451100 और 85451900 के अंतर्गत किया जाता है। तथापि, सम्बद्ध वस्तु को 38011000, 38019000, 83119000, 85354010, 85451100, 85451900, 85459090 तथा 85471090 जैसे प्रशुल्क शीर्षकों के अंतर्गत भी आयात किया जा रहा है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतक है और वर्तमान जांच के दायरे में अंतर्गत किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

3. आवेदक ने दावा किया है कि सम्बद्ध वस्तु जिसका चीन जन.गण. से भारत को निर्यात किया जाता है, तथा घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद दोनों समान वस्तुएं हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स तथा चीन से आयातित ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स दोनों अनिवार्य उत्पाद गुणधर्मों जैसे भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिक, कार्यों एवं प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन वस्तुओं के प्रशुल्क वर्गीकरण के तुलनीय हैं। उपभोक्ता गण इनका प्रयोग अदल बदल कर कर सकते हैं और कर रहे हैं। दोनों ही तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थानीय हैं और इसलिए उन्हें पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत "समान वस्तु" के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, भारत में आवेदनकर्ता द्वारा उत्पादित सम्बद्ध वस्तु को सम्बद्ध देश से आयातित सम्बद्ध वस्तु को "समान वस्तु" के रूप में माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग एवं आधार

4. यह आवेदनपत्र मैसर्स एच ई जी लिमिटेड तथा मैसर्स ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड द्वारा सामूहिक रूप से दायर किया गया है। यह नोट किया जाता है कि आवेदक गण देश में संबद्ध वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। अतः, याचिकाकर्ता आधार को संतुष्ट करते हैं और पाटनरोधी नियमावली के आशय के अंतर्गत वे घरेलू उद्योग बनते हैं। यह भी नोट किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का न तो आयात किया है और न ही वे विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबद्ध हैं। अतः यह निर्धारित किया जाता है कि यह आवेदन पत्र घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उनकी ओर से दायर किया गया है और यह आवेदनपत्र पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत "आधार" की अपेक्षाओं को संतुष्ट करता है। इसके अतिरिक्त, आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुरूप "घरेलू उद्योग" बनते हैं।

सम्बद्ध देश

5. वर्तमान जांच में शामिल सम्बद्ध देश चीन जन.गण है।

सामान्य मूल्य

6. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि चीन जन गण को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने सामान्य मूल्य का दावा, भारत में उत्पाद की लागत का विधिवत समायोजन करके इस आधार पर यह उल्लेख करते हुए किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश में लागत अथवा कीमत संबंधी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के दावे की जांच की है तथा नोट करते हैं कि सम्बद्ध देश में सम्बद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य है।

निर्यात कीमत

7. आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत का दावा, भारत में आयात की मात्रा एवं मूल्य का आकलन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस सूचना सेवा (आईबीआईएस) के आधार पर किया है। समुद्री भाड़ा, सामुद्रिक बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा व्यय और बैंक प्रभारों को ध्यान में रखते हुए कीमत समायोजन किया गया है। सम्बद्ध देश में सम्बद्ध वस्तु की निर्यात कीमत के प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है।

पाटन मार्जिन

8. आवेदक ने इस तथ्य के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं कि सम्बद्ध देश में सम्बद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से बहुत अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि सम्बद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है जो पाटनरोधी जांच शुरुआत को न्यायोचित ठहराता है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

9. आवेदकों ने दावा किया है कि उन्हें वास्तविक क्षति हुई है तथा उन्होंने सम्बद्ध देश से कथित पाटन के परिणाम स्वरूप उनको होने वाली क्षति का पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया है। यह दावा किया गया है कि सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु के आयातों में भारत में उत्पादन के संबंध में, कुल आयातों के संबंध में समग्र रूप से तथा भारत में सम्बद्ध वस्तु की कुल मांग के रूप में भारी वृद्धि हुई है। आवेदक ने विपरीत कीमत प्रभाव का दावा भी किया है जो कीमत निग्रहण एवं कीमत अधोरदन से स्पष्ट है। यह दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग के प्रचालनात्मक निष्पादन में लाभ, निवेश पर अर्जन, नकदी प्रवाह और कर पूर्व लाभ के रूप में गिरावट आई है। प्राधिकारी विचार करते हैं कि पाटनरोधी जांच शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए सम्बद्ध देश से सम्बद्ध वस्तु के पाटित आयातों द्वारा आवेदनकर्ता को पहुंचाई जा रही 'क्षति' के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

जांच की शुरुआत

10. प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सम्बद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सम्बद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को 'क्षति' तथा पाटन एवं 'क्षति' के बीच कारणात्मक संबंध में प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है जो पाटनरोधी जांच प्रारंभ करने को न्यायोचित ठहराते हैं। अतः, प्राधिकारी कथित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने, जो यदि लगाई गई तो

घरेलू उद्योग की 'क्षति' को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 में दी गई शर्तों के अनुरूप कथित पाटन तथा घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की एतद्वारा जांच प्रारंभ करते हैं।

जांच की अवधि

11. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि 1 जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012 है। तथापि, क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2009—मार्च, 2010 अप्रैल, 2010:मार्च, 2011, अप्रैल, 2011—मार्च, 2012 तथा जांच की अवधि (वीओआई) भी शामिल होगा।

सूचना प्रस्तुत करना

12 संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देश की सरकार को भारत स्थित उनके दूतावासों के जरिए, भारत में इस उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित स्वरूप और ढंग से अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। कोई भी हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय—सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से जांच से संगत निवेदन कर सकता है और उसे निम्नलिखित पते पर प्रेषित कर सकता है:—

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग, कमरा सं. 240,

उद्योग भवन

नई दिल्ली-110107

समय—सीमा

13 वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना और सुनवाई हेतु कोई भी अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों (चालीस दिनों) के भीतर पहुंच जाना चाहिए। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी नियमावली के अनुसरण में, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

14. सभी हितबद्ध पक्षकार पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(1) के अनुरूप प्रदान कराई गई गोपनीय सूचना के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 (2) के अनुसार उसका गोपनीय सूचना के अगोपनीय पाठ अथवा अगोपनीय सारांश में इतना पर्याप्त विवरण होना चाहिए कि वह अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सूचना की सार्थक समझ प्रदान कर सके। यदि सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकार की राय में उक्त सूचना का सारांश प्रस्तुत करना संभव नहीं है तो, उसके कारणों का विवरण उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा।

15. उपर्युक्त पैरा में किसी बात का उल्लेख होते हुए भी यदि प्राधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट है कि गोपनीयता का दावा आवश्यक नहीं है अथवा सूचना प्रदाता या तो सूचना को सार्वजनिक करने का अथवा इसे प्रकटन को सामान्यीकृत ढंग से या सार रूप में प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

16. पाटनरोधी अधिनियम के नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

17. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे.एस.दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Directorate General of Anti-dumping & Allied Duties)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2013

Subject: Initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of “Graphite Electrodes of all diameters” originating in or exported from China PR.

No.14/02/2013 – DGAD:—M/s HEG Ltd. and M/s Graphite India Ltd (hereinafter referred to as ‘petitioners’ or “the applicants”) have collectively filed an application (also referred to as petition) before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules) for initiation of Anti-Dumping Duty investigation concerning imports of Graphite Electrodes (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country). M/s HEG Ltd. and M/s Graphite India Ltd have provided relevant information.

Product under consideration

2. The product under consideration for the purpose of present investigation is “Graphite Electrodes of all diameters” from China PR. The main function of Graphite Electrodes is to be used for melting of steel by passing electric current into the charge fed into the furnaces. This method of steel making is also known as secondary steel making. Graphite Electrodes are used in arc furnaces as current carrying conductors and are required to carry a very high rate of power feed. Graphite electrodes can be broadly categorized as Ultra High Power (UHP) and others which include the High Power Grade (HPG) and Normal Power Grade (NPG). Accordingly, they are required to have properties capable for taking such high current and power feeds and classified under chapter heading 85.45. The product under consideration is primarily imported under 85451100 and 85451900. However, the subject goods are also being imported under tariff headings like 38011000, 38019000, 83119000, 85354010, 85451100, 85451900, 85459090 and 85471090. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Like Articles

3. The applicants have claimed that the subject goods, which are exported from China PR into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. Graphite Electrodes produced by the domestic industry and imported from China are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like article’ under the AD Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants in India are being treated as ‘Like Article’ to the subject goods being imported from the subject country.

Domestic Industry & Standing

4. The application has been collectively filed by M/s HEG Ltd. and M/s Graphite India Ltd. It is noted that the applicants accounts for total Indian production of subject goods in the country. Petitioners’ therefore, satisfy the standing and constitutes Domestic Industry within the meaning of the Rules. It is also noted that petitioner has neither imported the product under consideration from the subject country nor are they related to an importer or exporter of the product under consideration. It is thus determined that the application has been made by or on behalf of the domestic industry and the application satisfies the requirements of ‘standing’ under Rule 5 of the AD Rules. Further, the Applicants constitute ‘Domestic Industry’ in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

Subject Country

5. The subject country involved in the present investigation is China PR.

Normal value

6. The petitioner has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in accordance with para-7 of Annexure-I to the Rules. The petitioner has claimed normal value on the basis of cost of production in India, duly adjusted; stating that information on cost or price in a market economy third country is not publically available. The Authority examined the claim of the petitioner and notes that there is sufficient prima facie evidence of normal value of the subject goods in the subject country.

Export Price

7. The applicants have claimed export price for product under consideration based on International Business Information Services (IBIS), Mumbai to assess the volume and value of imports in India. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, port expenses, inland freight expenses and bank charges. There is sufficient prima facie evidence of export price of the subject goods in the subject country.

Dumping Margin

8. The applicant has provided sufficient evidence that the normal value of the subject goods in the subject country are significantly higher than the net export prices, prima-facie indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country are being dumped, to justify initiation of an anti-dumping investigation.

Injury and Causal Link

9. The applicants have claimed that they have suffered material injury and have furnished evidence regarding injury having taken place as a result of the alleged dumping from subject country. It has been claimed that Imports of subject goods from subject country have significantly increased in absolute terms, in relation to total imports, in relation to production in India and also in terms of total demand of the subject goods in India. . The applicant has also claimed adverse price effects as evidenced by price depression and price undercutting. It has also been claimed that operating performance of the domestic industry has deteriorated in terms of profits, return on investments, cash flow, and profit before interest. The Authority considers that there is sufficient evidence of 'injury' being suffered by the applicant caused by dumped imports of subject goods from subject country to justify initiation of an anti-dumping investigation.

Initiation of Investigations

10. The Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country, 'injury' to the domestic industry and causal link between the dumping and 'injury' exists to justify initiation of an anti-dumping investigation. The Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Period of Investigation

11. The period of investigation for the present investigation is from 1st January 2012 to December 2012. However, the injury investigation period will cover the periods April 2009-March 2010, April 2010-March 2011, April 2011 to March 2012 and the Period of Investigation (POI).

Submission of information

12. The known exporters in the subject country and their Governments through their Embassies in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time-limit set out below and write to:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
Room No. 240, Udyog Bhawan,
New Delhi -110107.

Time limit

13. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the AD Rules.

Submission of Information on Non-Confidential basis

14. All interested parties shall provide a confidential and non-confidential summary in terms of Rule 7 (2) of the AD Rules for the confidential information provided as per Rule 7 (1) of the AD Rules. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing information, such information is not susceptible to summary; a statement of reason thereof is required to be provided.

15. Notwithstanding anything contained in para above, if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information.

Inspection of Public File

16. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

17. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority